

१०

के पश्चात अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण जा उनके स्वर्गवास होने तक किसी भी रूप में निरस्त नहीं किया गया। मोतीसिंह के स्वर्गवास उनकी सहमति को प्रकट करती है। उक्त वसीयतनामा मोतीसिंह जी की अन्तिम इच्छा पत्र है, वसीयतनामा में मोतीसिंह की पत्नी मोहनकुंवर व पुत्री भवकंवर की साख जाली हुई है, जो उक्त आराजी की वसीयत अपीलान्त के पक्ष में निष्पादित की, जो रजिस्टर्ड है। उक्त द्वारा ही मोतीसिंह की सेवा सृष्टि की गई थी। इस कारण मोतीसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वारिदान में उनकी एकमात्र पुत्री भवकंवर व पत्नी मोहनकुंवर थी। अपीलान्त एवं उसके प्रति भोपालसिंह के काका लमाल थे। मोतीसिंह जी के कोई जायन्दा पत्र नहीं था। मोतीसिंह के 28, 29, 293 व 294 कायम हुए। मोतीसिंह जी संतोषकंवर के प्रति भगवतसिंह के दादा खसरा नम्बर 117, 118, 113, 114, 114सी, 241 व 241 सी0 के हाल खसरा नम्बर 22, 23, 27, हिस्सा था। उक्त सम्पत्ति मोतीसिंह जी की स्व-अर्जित सम्पत्ति थी। सेटलमेन्ट के पश्चात गत खसरा नम्बर 117, 118, 113, 114, 114सी, 241 व 241 सी0 की भूमि में मोतीसिंह का 1/2

वकील अपीलान्त ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम ऐलानी के पुराने किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सजी गई। सज्जद टू लामिदेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्योडेन्ट जारिये सम्मन व अपीलार्थीन रेकॉर्ड तलब होने से धारा 5 लामिदेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील देसूरी पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 04.08.1999 के विरुद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम ऐलानी के नामान्तरकरण संख्या 36 पर तहसीलदार अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान दिनांक :- 25/02/2019

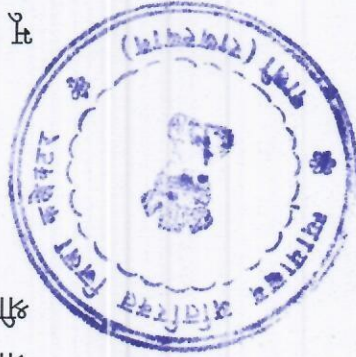
--: निर्णय :-

श्री खीमाराम, सरकारी वकील

श्री सुभरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिषाक, रेस्योडेन्ट संख्या 1

श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिषाक अपीलान्त

उपस्थित



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

- | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
| 1. रघुराजसिंह तथाकथित गाद पत्र मोतीसिंह | श्रीमती संतोषकंवर पत्नी भगवतसिंह | तहसील रानी जिला पाली |
| 2. तहसीलदार देसूरी | जालि राजपूत निवासी ऐलानी | |
| 3. तहसीलदार रानी | जन्मदाता पिता परबतसिंह जालि राजपूत | |
| | निसासी ऐलानी तहसील रानी | |

RCMS Case No. 2018/00295

राजस्थान अपील : 36/2017

पीठाधीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

न्यायालय आतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

Section 5 - Condonation of delay - Sufficient cause - Courts directed to make justifiably liberal approach in the matter - Doctrine of equality - States cannot be given stepmotherly treatment." एषी विरुद्ध रूप से पैरा संख्या 3 में उद्धरित किया है, जो इस प्रकार है - 3—The legislature has conferred the power to condone delay by enacting Section 5 "Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of 0. XXI of the Civil Procedure Code, 1908, may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfies the Court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period." of the Indian Limitation Act of 1963 in order to enable the Courts to do substantial justice to parties by disposing of matters on 'merits'. The expression "sufficient cause" employed by the legislature is adequately elastic to enable the Courts to apply the law in a meaningful manner which subserves the ends of justice that being the life-purpose for the existence of the institution of Courts. It is common knowledge that this Court has been making a justifiably liberal approach in matters, instituted in this Court. But the message does not appear to have percolated down to all the other Courts in the hierarchy. And such a liberal approach is adopted on principle as it is realised that :-

1. Ordinarily a litigant does not stand to benefit by lodging an appeal late.
2. Refusing to condone delay can result in a meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause of justice being defeated. As against this when delay is condoned the highest that can happen is that a cause would be decided on merits after hearing the parties.
3. "Every day's delay must be explained" does not mean that a pedantic approach should be made. Why not every hour's delay every second's delay ? The doctrine must be applied in a rational common sense pragmatic manner.
4. When substantial justice and technical considerations are pitted against each other, cause of substantial justice deserves to be preferred for the other side claim to have vested right in injustice being done because of a non-deliberate delay.
5. There is no presumption that delay is occasioned deliberately, or on account of culpable negligence, or on account of *mala fides*. A litigant does not stand to benefit by resorting to delay. In fact he runs a serious risk.
6. It must be grasped that judiciary is respected not on account of its power to legalise injustice on technical grounds but because it is capable of removing injustice and is expected to do so.

Making a justice-oriented approach from this perspective, there was sufficient cause for condoning the delay in the institution of the appeal. The fact that it was the State, which was seeking condonation and not a private party was altogether irrelevant. The doctrine of equality before law demands that all litigants, including the State as a litigant, are accorded the same treatment and the law is administered in an even-handed manner. There is no warrant for according a stepmotherly treatment when the 'State' is the applicant praying for condonation of delay. In fact experience shows that on account of an impersonal machinery (no one in charge of the matter is directly hit or hurt by the judgment sought to be subjected to appeal) and the inherited bureaucratic methodology imbued with the note-making, file pushing, and passing on the buck ethos, delay on its part is less difficult to understand though more difficult to approve. In any event, the State which represents the collective cause of the community, does not deserve a litigant *non grata* status. The Courts therefore have to be informed with the spirit and philosophy of the provision in the course of the interpretation of the expression "sufficient cause". So also the same approach has to be evidenced in its application to matters at hand with the end in view to do



~~राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर~~

even-handed justice on merits in preference to the approach which scuttles a decision on merits. Turning to the facts of the matter giving rise to the present appeal, we are satisfied that sufficient cause exists for the delay. The order of the High Court dismissing the appeal before it as time barred, is therefore, set aside. Delay is condoned. And the matter is remitted to the High Court. The High Court will now dispose of the appeal on merits after affording reasonable opportunity of hearing to both the sides. इसी प्रकार माननीय राजस्व मंडल द्वारा आर0आर0टो 2004 (2) पैज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मरिट पर निर्णित करने चाहिए - तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिए।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारमूल प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार अपीलानुवृत्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिशीला अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब प्रकरण को गुणावर्गण के आधार पर देखा जाता है, तो निम्न स्थिति प्रकट होती है कि प्रकरण में अपीलानुवृत्त द्वारा जैर अपील विवाहित आराजी को मोतीसिंह की स्व-अर्जित सम्पत्ति होना बताते हुए स्वयं के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दायर करवाने का अर्जलिष थाहा, जबकि रेस्पॉडेन्ट द्वारा उक्त मूिम मोतीसिंह की स्व-अर्जित नहीं होकर धैरक होना बताते हुए मोतीसिंह को वसीयत करने का अधिकार नहीं होना कथन करते हुए अपील को खारिज कराने का निवेदन किया। जहां तक वसीयत का प्रश्न है, तो उक्त वसीयत माननीय स्थित न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत होने के कारण, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं है, किन्तु जहां तक वसीयत के प्रभावी होने का प्रश्न है, तो यह सुस्थापित है कि वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होते हैं तथा वसीयतकर्ता की मृत्यु होने पर वसीयत की गई सम्पत्ति वसीयतग्रहिता को समर्पित हो जाती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया, वह विधिक दृष्टिकोण से उचितपूर्ण नहीं था।

परिणाम स्वरूप अपीलानुवृत्त द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम ऐलानी के नामान्तरकरण संख्या 36 पर तहसीलदार देसैरी पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 04.08.1999 को अपस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वसीयतनामा के आधार पर जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। मूल नामान्तरकरण एवं निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार रानी को प्रेषित की जावे।

~~आतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
(भागीरथ बिश्नाई)~~

निर्णय आज दिनांक 25/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद इस्तेमाल कर खूले न्यायालय में सुनाया गया।

~~आतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
(भागीरथ बिश्नाई)~~

